Factory Chandrapur due to the proposed mining in Baranj Block. On receipt of this advise the Ministry of Defence was informed that coal mining in 40 mines with a total reserve of about 1000 million tonnes is going on within a raius of 25 kms from the ordnance Factory, Chandrapur for production of 18 million tonnes of coal per year in the past several years by WCL and that Ministry of Coal was not advised over the past three decades of any adverse effect of such mining activity on the Ordnance Factory. Ministry of Defence was also requested to inform the Ministry of Coal on the law prohibiting mining operations within a radius of 25 kms from ordnance Factories. No reply from Ministry of Defence has been received in Minisry of Coal thereafter.

(d) and (e) As no specific Act has been referred to in part (a) to (c) of the question, it is presumed that the Hon'ble Member is referring to the Mines and Minerals (Regulation and development) Act or the Explosives Act. The former deals with mining leases and related matters and the latter with the use of Explosives. These laws are applicable in all parts of the country, and the violation of any of the provisions will be dealt with as per law.

अगले दस वर्षों में कोयले की मांग

469. **श्री अजीत जोगी:**

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी दस वर्षों में उद्योगों तथा विद्युत उत्पादन की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु कोयले की कुल अनुमानित मांग कितनी होगी और इसके अनुमानित उत्पादन हेतु सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना पूंजीनिवेश किए जाने का विचार है;

(ख) मध्य प्रदेश में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) कोयले के इन भंडारों के खनन हेतु आगामी पांच वर्षों में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट में किए गए मूल्यांकन के अनुसार उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने हेतु तथा विद्युत का उत्पदान किए जाने के लिए अपेक्षित कोयले की मांग नीचे दर्शाई गई है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग
2001-02	405.00
(नौवीं पंचवर्षीय योजना का अंन्तिम वर्ष)	
2006-07	563.00
(दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूंजी निवेश का अनुमान नहीं लगाया गया है अथवा न ही निजी क्षेत्र में प्रस्तावित किए गए पूंजी निवेश प्रक्षिप्त किए गए हैं। किन्तु कोयला और लिग्नाइट पर कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 339 मिलियन टन कोयले और 29.5 मिलियन टन लिग्नाइट के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं 22,206 करोड़ रुपये की राशि की है।

(ख) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में कोयले के अनुमानित भंडार नीचे दर्शाए गए हैं:—

(मिलियन टन में)

प्रणाणित	इंगित	अनुमानित	जोड़
10762.37	21864.55	8824.29	41451.21

(ग) प्रौद्योगिकी आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर नई कोयला परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य में कोयला कंपनियों द्वारा 4591.25 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किये जाने का अनुमान लगाया गया है।

कोयला खानों को बंद किया जाना

470. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरेजवाला:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिन्हें कोयला होने के बावजूद कतिपय अन्य कारणों से बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार इन बंद पड़ी खानों में से कुल कोयला खानों को फिर से चालू करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस समय बंद पड़ी खानों को फिर से चालू करने के लिए इन्हें निजी उद्यमियों को सौंपने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को० इ० लि०) की 29 कोयला खानें और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (सि० को० कं० लि०) की 2 खानों को खनन योग्य भंडारों का परिसमापन होने के कारणों के अलावा अन्य कारणों से बंद कर दिया गया था।

(ख) को० ई० लि० और सि० को० कं० लि० का इन बंद पड़ी खानों को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भाग (ख) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) इन खानों को प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थितियों, सुरक्षा कारणों और तकनीकी—आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण बंद कर दिया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

Theft of coal in Western India Coal Field in Nagpur

471. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there has been a number of complaints of theft of coal in the Western India Coal Field in Nagpur; and

(b) if so, the details of the theft and action taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) On the basis of raids carried out by Security Personnel and through joint raids with state law and order authorities, 16 cases of theft involving 105.68 MT of coal have come to notice in WCL in 1996-97. In all the cases FIRs were lodged with the police and 9 persons were arrested.

Development of coal mines

472. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the specific steps taken by Government in Eighth Plan for the development of coal mines;

(b) the steps taken by Mahanadi Coalfields limited for the development of coal reserves in Orissa during last three years; and

(c) the proposal mooted thereon in the Ninth Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Coal production increased from 238.11 Million Tonnes in 1992-93 to 288.65 Million Tonnes in 1996-97. Futher, regional exploration was conducted for 1374.5 Sq. Kms as against the target of 1200 Sq. Kms. Similarly 3,63 lakh metres of drilling was carried out under regional as well as promotional exploration schemes as against the target of 3.04 lakh metres. As a consequence